भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4834

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरिकी पारस्परिक शुल्क का प्रभाव

4834. श्री मनीश तिवारी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को भारत सहित अन्य देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने के संबंध में अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा की जानकारी है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके उक्त पारस्परिक शुल्क से प्रभावित होने की संभावना है और भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को इससे होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान का आकलन क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भारतीय व्यापार और वाणिज्य पर उक्त शुल्क के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कोई बातचीत या कूटनीतिक भागीदारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या प्रस्तावित अमेरिकी शुल्क के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि में 0.1 से 0.6 प्रतिशत की कमी आ सकती है जैसा कि गोल्डमैन सैक् ने रिपोर्ट किया है; और
(ङ) भविष्य में इस प्रकार के व्यापारिक व्यवधानों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) : अमेरिका ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को पारस्परिक व्यापार और प्रशुल्क संबंधी ज्ञापन जारी किया जिसमें वाणिज्य सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि व्यापारिक भागीदारों द्वारा अपनाई गई किसी भी गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्था से अमेरिका को हानि की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और प्रत्येक व्यापारिक भागीदार के लिए विस्तृत प्रस्तावित उपायों के साथ एक रिपोर्ट प्रदान करेंगे, जिसके आधार

पर संबंधित व्यापारिक भागीदार के विरुद्ध अमेरीका द्वारा कार्रवाई किसी सुसंगत अमेरीकी कानूनों के अंतर्गत की जा सके। वर्तमान तिथि तक, अमेरीका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी,बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत दोनों देश बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने और प्रमुख व्यापार मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

(ग) से (ङ): भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर वार्ता करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ निरंतर कार्य कर रही हैं जिसके अंतर्गत दोनों देश बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, आपूत श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने और प्रमुख व्यापार मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

****